PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्षः 12 | अंकः 316 | मूल्यः 1.00 रुपए | पृष्ठः 4 | सोमवार 01 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

सरकार का 'साइलेंट अटैक'

भाटी-बेनीवाल पर वार

अपनों पर मेहरबान !

विपक्ष ने दोहरे मापदंड अपनाने और अपने मंत्री को बचाने के लगाए गंभीर आरोप

सियासी संघर्ष, तीखे जनांदोलनों और विवादित बयानों पर सरकार बिना किसी बड़े तामझाम या सीधे टकराव के पर्दे के पीछे से कर रही प्रशासनिक और कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

राजस्थान की धरा एक बार फिर सियासी संघर्ष और जनांदोलनों की तपिश से सुलग उठी है। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति के दो सबसे बड़े ध्रुव निर्दलीय विधायक रविंद्रसिंह भाटी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सरकार के सामने सीना ताने खड़े हैं। बाड़मेर की गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों के हक से लेकर प्रदेश के स्थानीय युवाओं के रोजगार तक, आंदोलनों के इस 'एक्शन रिप्ले' ने प्रदेश की भजनलाल सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ, इन आंदोलनों के बाद हुए प्रशासनिक फेरबदल, सुरक्षा में कटौती और पुलिसकर्मियों के निलंबन ने इस आग में घी डालने का काम किया है। राजस्थान की धरा पर पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी संघर्ष, तीखे जनांदोलनों और विवादित बयानों के बीच अब राज्य की भजनलाल सरकार ने एक नई और बेहद आक्रामक रणनीति अपना ली है। राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार का 'साइलेंट अटैक' कहा जा रहा है। सरकार बिना किसी बड़े तामझाम या सीधे टकराव के पर्दे के पीछे से ऐसी प्रशासनिक और कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है जिससे बड़े-बड़े आंदोलनकारियों और दिग्गज नेताओं के हौसले पस्त होने लगे हैं। चाहे वो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का 'पेट्रोल कांड' आंदोलन हो या आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के तीखे तेवर, सरकार ने सीधी बयानबाजी करने के बजाय सीधे प्रशासनिक हंटर चलाने का रास्ता चुना है। हालांकि अपनों पर मेहरबानी से सरकार की आलोचना भी हो रही है।

रणनीति : विपक्ष और आंदोलनकारियों को घेरने का नया फॉर्मूला -

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भजनलाल सरकार का यह 'साइलेंट अटैक' काफी सोच-समझकर तैयार किया गया है। इसके तीन मुख्य उद्देश्य नजर आ रहे हैं। नेताओं को अलग-थलग करना, यानि सुरक्षा हटाकर या करीबियों पर कार्रवाई करके नेताओं को दबाव में लाना। प्रशासन को कड़ा संदेश, यानि किसी भी अफसर द्वारा आंदोलनकारियों को रियायत देने पर सीधे निलंबन या तबादले की गाज गिरना। कानून व्यवस्था का डंडा, यानि बिना किसी बड़े राजनीतिक हंगामे के चुपचाप कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना ताकि विपक्ष को सीधा मुद्दा न मिल सके।

टूटे रीढ़, ऐसा है सरकार का 'साइलेंट अटैक' -

इस पूरी रणनीति को अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार किसी भी आंदोलनकारी नेता को सीधे गिरफ्तार करके 'हीरो' बनने का मौका नहीं दे रही है। इसके बजाय सरकार उन कड़ियों पर वार कर रही है जिससे आंदोलन की रीढ़ ही टूट जाए।

इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पर अपनों को ही सजा -

बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी के पेट्रोल छिड़कने की घटना के बाद इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा फोड़ते हुए खुद भाटी के पीएसओ तखत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इससे यह संदेश गया कि आंदोलन के दौरान अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई बेहद सख्त होगी।

सुरक्षा कवच पर सीधा वार (कवच हुआ फीका) -

हनुमान बेनीवाल द्वारा सरकार और पुलिस के खिलाफ तीखी बयानबाजी के तुरंत बाद प्रशासन ने उनके सुरक्षा बेड़े से 3 पीएसओ हटा दिए। इससे पहले रविंद्र सिंह भाटी के भी पीएसओ हटा लिए गए थे। यह नेताओं को सीधा संदेश है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मिलने वाली विशेष सुविधाएं तुरंत वापस ली जा सकती हैं।

मददगारों और अफसरों का तत्काल सफाया

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को काले झंडे दिखाए जाने के मामले में लापरवाही बरतने वाले एसएचओ को तुरंत सस्पेंड किया गया। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को तुरंत जमानत देने वाले तहसीलदार और जिले के एसपी का रातों-रात ट्रांसफर कर दिया गया। यह स्थानीय प्रशासन के लिए खुली चेतावनी है कि आंदोलनकारियों के प्रति कोई भी नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

काले झंडे, सस्पेंशन और तबादलों का दौर

आंदोलन की आंच केवल बाड़मेर तक सीमित नहीं है। आरएलपी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के आक्रोश के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को काले झंडे दिखाए जाने की घटना भी सामने आई। इस सुरक्षा चूक के बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी (स॥ह्) को सस्पेंड कर दिया। मामला यहीं नहीं रुका, आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले तहसीलदार और जिले के एसपी का भी आनन-फानन में ट्रांसफर कर दिया गया। इन ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि सरकार इन आंदोलनों को दबाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपना रही है।

'पेट्रोल कांड' से दहला बाड़मेर, झुकी नहीं सरकार

बाड़मेर की गिरल कोयला खदान (लिग्नाइट माइंस) के मजदूरों के हक और बेहतर वेतन-रोजगार की मांगों को लेकर शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्रसिंह भाटी पिछले कई दिनों से मोर्चे पर डटे हुए हैं। आंदोलन उस समय एक बेहद संवेदनशील और खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया, जब कलेक्ट्रेट कूच के दौरान विधायक भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। इस 'पेट्रोल कांड' के बाद पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। सरकार को जगाने के लिए भाटी ने गृहमंत्री को अपने खून से चिट्ठी भी लिखी, लेकिन इसके बावजूद जब वार्ता पूरी तरह बेनतीजा रही, तो भाटी ने धरना स्थल पर 'सद्बुद्धि यज्ञ' शुरू कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि जेल भेजकर हमें दबा दोगे, यह सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस रामराज्य सरकार में राजा सो रहा है और जनता त्रस्त है।

बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ खोला तीखा मोर्चा

एक तरफ जहां बाड़मेर में भाटी का आंदोलन उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति के 'तेजा' कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल का तेवर भी तीखा बना हुआ है। बेनीवाल ने हाल ही में प्रदेश में बढ़ते नशे, रोजगार की कमी और स्थानीय उद्योगों में 80% नौकरियों पर बाहरी लोगों के कब्जे को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा मोर्चा खोला है। हालांकि, इस राजनीतिक खींचतान के बीच हनुमान बेनीवाल के सुरक्षा कवच में कटौती कर दी गई है। उनकी बयानबाजी और तीखे तेवरों के ठीक बाद प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सियासी गलियारों में इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस बात की भी पुरजोर चर्चा है कि जहां बेनीवाल के दबाव के आगे प्रशासन चंद घंटों में घुटने टेक देता है, वहीं भाटी के लंबे आंदोलन और 'खून की चिट्ठी' के बाद भी सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है।

खुद के मंत्री पर 'मेहरबानी' का आरोप -

राजस्थान की राजनीति में आंदोलनों के इस 'एक्शन रिप्ले' के बीच अब विपक्ष ने भजनलाल सरकार की प्रशासनिक कार्रवाइयों पर दोहरे मापदंड अपनाने और अपने मंत्रियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां एक तरफ जनहित के मुद्दों को उठाने वाले नेताओं के खिलाफ सरकार सख्त दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ के डूंगला थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौज और अभद्रता के आरोपी सहकारिता मंत्री गौतम दक पर सरकार की विशेष मेहरबानी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष और जनता पूछ रही है कि जब आम कार्यकर्ताओं और छोटे पुलिसकर्मियों पर तुरंत गाज गिर सकती है, तो कथित रूप से मर्यादा लांघने वाले मंत्री पर अब तक सरकार चुप क्यों है। मामले के तूल पकड़ने के बाद डूंगला थानाधिकारी शैतान सिंह ने पूरी बहादुरी दिखाते हुए मंत्री गौतम दक के खिलाफ राजकार्य में बाधा, शांति भंग करने और पुलिसकर्मियों का घोर अपमान करने की धाराओं के तहत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करवाई है। थानाधिकारी ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि मंत्री की इस अभद्रता और धमकियों की वजह से वे और उनका पूरा पुलिस स्टाफ गहरे अवसाद में है। इस कथित 'मेहरबानी' और दोहरी नीति को लेकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने भजनलाल सरकार की घेराबंदी कर दी शुरू कर दी है।

बेनीवाल का तीखा पलटवार - 'भजनलाल सरकार मेरी सुरक्षा क्या करेगी?' -

सुरक्षा में कटौती के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। मीडिया बातचीत में बेनीवाल ने कहा, 'मैंने तो सरकार से कभी सुरक्षा मांगी ही नहीं थी। भजनलाल सरकार मेरी सुरक्षा क्या करेगी? मैंने बजरी माफिया और पेपर लीक जैसी बड़ी ताकतों से लड़ाई लड़ी है। मेरी असली सुरक्षा प्रदेश के हजारों युवा हैं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं।' बेनीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उन्हें जयपुर में किसी बड़े विवाद या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश में फंसाना चाहती थी, जिसे उन्होंने अपनी समझदारी से टाल दिया।

भाटी बोले- जेल भेजकर हमें दबा दोंगे, ये गलतफहमी

बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर चर्चा में हैं। 19 मई को बाड़मेर कलेक्ट्रेट में खुद पर पेट्रोल छिड़कने के 10 दिन बाद उनके पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) नखत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। भाटी का कहना हैं- यह मेरे पीएसओ का नहीं, पूरे सिस्टम का फेलियर है। 19 मई के दिन कलेक्ट्रेट पर पूरा पुलिस जाब्ता, जिला प्रशासन के बड़े-बड़े अधिकारी, एसपी से लेकर एएसपी, डीएसपी, मौका मजिस्ट्रेट, डीएसटी टीम मौजूद थी। लेकिन पूरा इंटलीजेंस फेल रहा। जिम्मेदार अफसरों ने अपने फेलियर और नाकामियों को दबाने के लिए एक निर्दोष कर्मचारी (पीएसओ) के खिलाफ कार्रवाई की। अगर उन्हें लड़ाई लड़नी है, तो मेरे से लड़नी चाहिए, मैं कबड्?डी खेलने के लिए तैयार हूं। आज भी और कल भी तैयार रहूंगा।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

कर्नाटक में परिवर्तन

त्यागपत्र देने को तैयार हुए सिद्धरमैया ने यह तो माना कि आलाकमान ने जैसा कहा, वैसा किया, पर वे राज्यसभा आने को तैयार नहीं।

आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने त्यागपत्र दे दिया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उनकी जगह आसीन होने का रास्ता साफ हो गया। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा लंबे समय से हो रही थी और इसे लेकर खींचतान भी जारी थी, लेकिन कुछ तय नहीं हो पा रहा था। शिवकुमार का दावा था कि 2023 में सरकार गठन के समय सिद्दरमैया और उनके बीच ढाई-ढाई वर्ष तक सत्ता संभालने की सहमति बनी थी, पर कांग्रेस नेतृत्व ने इसकी पुष्टि नहीं की। अब तीन वर्ष बाद नेतृत्व परिवर्तन होना यह बताता है कि वास्तव में दोनों नेताओं में बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने का समझौता हुआ था और उससे कांग्रेस आलाकमान भी अवगत था। यदि ऐसा था तो फिर छह माह की देरी क्यों हुई? यह प्रश्न कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी की विफलता को दर्शाता है। इसलिए और भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन तब सुनिश्चित हो पाया, जब प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया। यदि यह सच है तो यह पुराना सवाल फिर से उठेगा कि आखिर राहुल गांधी समय पर फैसला क्यों नहीं ले पाते? ध्यान रहे कि कांग्रेस अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खरगे हों, लेकिन पार्टी के बड़े फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। त्यागपत्र देने को तैयार हुए सिद्दरमैया ने यह तो माना कि आलाकमान ने जैसा कहा, वैसा किया, पर वे राज्यसभा आने को तैयार नहीं। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को यह संदेश दिया कि वे संतुष्ट नहीं हैं और अपने हिसाब से राज्य की ही राजनीति करेंगे। हालांकि उनके त्यागपत्र देने पर शिवकुमार ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन यह कहना बहुत कठिन है कि दोनों के रिश्ते सामान्य बने रहेंगे और कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसकी अनदेखी न की जाए कि इसके पहले बारी-बारी से नेतृत्व करने को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी तरह की खींचतान हुई थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ढाई-ढाई साल तक सत्ता संभालने को लेकर तनातनी जारी रही तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच। कांग्रेस नेतृत्व न तो इन दोनों राज्यों में अपने नेताओं के झगड़े को सुलझा पाया और न ही यह साफ कर पाया कि उनमें ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहने का समझौता हुआ था या नहीं? पंजाब में उसने नवजोत सिंह सिद्धू को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पद छोड़ने के लिए बाध्य किया तो इसके नतीजे में वहां ऐसी गुटबाजी पनपी कि पार्टी को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा पाई। कर्नाटक में क्या होगा, यह दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव ही बताएंगे।

ईएमआई पर भी महंगाई का असर

पवन कुमार गुर्जर

अमेरिका-ईरान युद्ध का असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। देश में हाल ही में महज 10 दिनों में चार बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जिससे जनता भी काफी परेशान भी नजर आ रही है। इसके अलावा सोने- चांदी पर भी आयात शुल्क को बढ़ाया गया है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये परेशानी आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है. जिसको लेकर अब RBI भी सतर्क हो गया है। अर्थशास्त्रियों ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। इन फैसलों के कारण जून 2026 तक खुदरा महंगाई दर भी बढ़कर 5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सामान ढुलाई की लागत बढ़ जाती है।जिसका असर रोजमर्रा की चीजों, सब्जियों, खाद्य पदार्थों और बिजली जैसी सुविधाओं पर भी पड़ता है। इससे आम उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। RBI फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जून में होने वाली मौनेटरी नीति कमेटी की बैठक में RBI रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है। हालांकि, अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही और 5 प्रतिशत के ऊपर जाने लगी, तो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई मुख्य रूप से सप्लाई और ईंधन लागत से जुड़ी हुई है। ऐसे में सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर तुरंत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। RBI पहले ये देखना चाहता है कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर बाजार और उपभोक्ताओं पर कितना पड़ता है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी भी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कई एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर करीब 5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही आर्थिक विकास दर के अनुमान में भी कटौती की आशंका जताई जा रही है।

जेन-जी, सोशल मीडिया और संचार के उबलते सवाल

भारत में 'कॉकरोच जनता पार्टी' का प्रसंग केवल एक न्यायिक टिप्पणी पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह आज के जनसंचार, सोशल मीडिया और युवा मनोविज्ञान की बदलती प्रकृति को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह डिजिटल अभियान सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसे बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं और मीडिया से जुड़े लोगों के संदर्भ में 'कॉकरोच' जैसी तुलना के रूप में ग्रहण किया गया। बाद में इस टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण और वापसी की बात भी सामने आई, लेकिन तब तक यह शब्द सोशल मीडिया पर एक प्रतीक बन चुका था।

युवाओं के गंभीर सवाल और व्यंग्य

इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शब्द को अपमान की तरह लिया गया, उसी को युवाओं ने व्यंग्य और प्रतिरोध की पहचान में बदल दिया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने स्वयं को 'आलसी और बेरोजगारों की आवाज' जैसे व्यंग्यात्मक नारे से प्रस्तुत किया। यह नाम भले हास्यपूर्ण लगे, लेकिन इसके भीतर बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा, मीडिया स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे गंभीर प्रश्न छिपे हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह अभियान कुछ ही दिनों में लाखों-करोड़ों डिजिटल फॉलोअर्स तक पहुंचा और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और राजनीतिक विमर्श बदलने की कोशिश बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इससे जुड़े 70 प्रतिशत सदस्य 19 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बताए गए हैं। यह प्रसंग बताता है कि आज जनसंचार का स्वरूप ऊपर से नीचे की ओर नहीं रहा। पहले समाचार संस्थान, राजनीतिक दल या सत्ता संस्थान विमर्श तय करते थे। अब एक वाक्य, एक मीम, एक हैशटैग या एक छोटा सा वीडियो भी बहस की दिशा बदल सकता है। सोशल मीडिया ने सामान्य नागरिक को केवल दर्शक नहीं रहने दिया, वह निर्माता, प्रसारक और प्रतिवादी तीनों बन गया है। यहां 'कॉकरोच' शब्द का उलट प्रयोग विशेष अध्ययन का विषय है। अपमानजनक प्रतीक को आंदोलनकारी प्रतीक में बदलना नई पीढी की डिजिटल भाषा की खासियत है। पुराने आंदोलनों में पोस्टर, नारे, पर्चे और जनसभाएं प्रमुख माध्यम थे। आज मीम, रील, एक्स पोस्ट, इंस्टाग्राम हैंडल, लाइव स्ट्रीम और डिजिटल सदस्यता नए पर्चे और पोस्टर हैं। लेकिन इस ताकत के साथ खतरे भी हैं। हिसार पुलिस और साइबर सेल ने इस अभियान की लोकप्रियता का लाभ उठाकर चलाए जा रहे फर्जी सदस्यता लिंक और फिशिंग संदेशों को लेकर चेतावनी दी है। यानी कोई भी वायरल भावनात्मक लहर साइबर ठगी, डेटा चोरी और वित्तीय अपराध का माध्यम भी बन सकती है। इसलिए 'कॉकरोच जनता पार्टी' को केवल हास्य या क्षणिक वायरल ट्रेंड समझना भूल होगी। यह डिजिटल युग में सम्मान, असंतोष और प्रतिनिधित्व की नई भाषा का संकेत है। क्या यह भारत में जेन-जी की राजनीतिक प्रतिक्रिया है? इस प्रश्न का उत्तर सावधानी से देना होगा। 'कॉकरोच जनता पार्टी' को सीधे राजनीतिक क्रांति कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इसे जेन-जी की बेचैनी, हताशा और प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया के रूप में अवश्य देखा जा सकता है। जेन-जी वह पीढी है जो इंटरनेट, मोबाइल, मीम संस्कृति, त्वरित प्रतिक्रिया और दृश्य संचार के साथ बड़ी हुई है। यह पीढी लंबी विचारधारात्मक किताओं की जगह छोटे, तीखे और प्रतीकात्मक संदेशों से जुडती है। राइटर्स की रिपोर्ट में इस अभियान को भारत के जेन-जी की चिंताओं से जोड़ते हुए बेरोजगारी, आर्थिक तनाव और जीवन निर्णयों में देरी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में 15-29 आयु वर्ग में बेरोजगारी और आर्थिक दबावों की चिंता को भी इस पृष्ठभूमि से जोड़ा गया। भारत के आसपास पिछले कुछ वर्षों में युवा आंदोलनों ने सत्ता और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन ने कोटा व्यवस्था के विरोध से शुरुआत की और बाद में वह व्यापक राजनीतिक असंतोष में बदल गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इसी असंतोष के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़ा।

युवा आंदोलनों और राजनीतिक बदलावों के वैश्विक उदाहरण

नेपाल में 2025 में सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में जेन-जी आंदोलन भड़का। राइटर्स और गार्जियन की रिपोर्टों के अनुसार सरकार द्वारा कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर रोक के बाद युवाओं में भारी गुस्सा फैला, प्रदर्शन हिंसक हुए, लोगों की जान गई और अंतत: प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका का 2022 का 'अरगलया' आंदोलन भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कार्नेगी एंडोवमेंट के अध्ययन के अनुसार यह आंदोलन आर्थिक कठिनाइयों, भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के विरुद्ध व्यापक जनाक्रोश से पैदा हुआ था, न कि किसी एक राजनीतिक विचारधारा से। फ्रीडम हाउस ने भी लिखा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिये लामबंद हुए और आंदोलन व्यापक राजनीतिक सुधार की मांग में बदल गया।

वैश्विक आंदोलनों से सीधा मुकाबला क्यों नहीं?

इन उदाहरणों की रोशनी में भारत की स्थिति को समझना चाहिए। भारत का लोकतंत्र कहीं अधिक बड़ा, संस्थागत और बहुस्तरीय है। यहां चुनावी राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया, संघीय ढांचा और नागरिक समाज के अनेक मंच हैं। इसलिए किसी वायरल डिजिटल अभियान की तुलना सीधे नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका से करना उचित नहीं होगा। फिर भी यह संकेत अवश्य है कि युवा वर्ग अपने सम्मान, रोजगार, अवसर, अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व को लेकर अधिक संवेदनशील है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जेन-जी की भाषा में राजनीतिक व्यंग्य है। यह पारंपरिक भाषण नहीं, बल्कि मीम आधारित राजनीतिक प्रतिक्रिया है। यह नाराजगी भी है, हास्य भी है, अविश्वास भी है और संवाद की मांग भी।

देश को अस्थिर करने वाली ताकतें तो नहीं?

इस प्रश्न पर संतुलित दृष्टि जरूरी है। किसी भी तेजी से फैलते डिजिटल अभियान में बाहरी हस्तक्षेप, बॉट नेटवर्क, फर्जी अकाउंट, डेटा हेराफेरी और साइबर दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी आंदोलन या अभियान को बिना ठोस प्रमाण 'राष्ट्रविरोधी साजिश' कहना भी उतना ही खतरनाक है। इसकी और अधिक तीव्र और विपरीत प्रतिक्रिया भी हो सकती है। कुछ राजनीतिक नेताओं ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की भौगोलिक स्थिति को लेकर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि बहुत बड़ी संख्या में इसके फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और भारत से कम हैं। हालांकि यह दावा मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्टों में स्वतंत्र रूप से या तकनीकी आधार पर इसका सत्यापन या पुष्टि नहीं हुई है।

पटरी पर लौटता तीन भाषा फॉर्मूला

प्रेमपाल शर्मा

सीबीएसई और केंद्र सरकार के ताजा निर्णय की तारीफ की जानी चाहिए, जिसमें उन्होंने नौवीं कक्षा में दो भारतीय भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य किया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन का अगला कदम है। सीबीएसई के नए आदेश के अनुसार पहली जुलाई से देश में नौवीं कक्षा में तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें दो अनिवार्य रूप से भारतीय भाषाएं होंगी। अगर पहली भाषा अंग्रेजी है तो दूसरी भाषा हिंदी या अपनी मातृभाषा होगी और तीसरी भाषा के रूप में विद्यालय संविधान की आठवीं अनुसूची की कोई भी भाषा चुन सकते हैं। इसका उद्देश्य बहुभाषी समाज की तरफ बढ़ना है, जो इस देश की हकीकत भी है। 1960 के दशक में कोठारी आयोग द्वारा दिए गए तीन भाषा सूत्र का आत्मा भी यही था कि उत्तर भारत के बच्चे दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें और दक्षिण भारत के बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा उत्तर भारत की हिंदी सीखें, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इसे हिंदी थोपने के रूप में दुष्प्रचार किया गया। उत्तर भारत की शिक्षा नीति में भी यह कमी रही कि उसने दक्षिण की कोई भाषा सीखने के बजाय तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत से काम चला कर खानापूर्ति कर ली। उम्मीद है उत्तर भारत अब ऐसी गलती नहीं करेगा। दक्षिण भारत का इसीलिए आज तक यह विरोध जारी है कि जब उत्तर भारत उसकी कोई भाषा नहीं सिखाता तो दक्षिण के राज्य भी हिंदी क्यों सीखें? इसीलिए तीन भाषा फार्मूला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। अब सरकार की नई सुविचारित नीति के तहत यह सफल होता नजर आ रहा है। वर्तमान में उत्तर भारत में विशेषकर अधिकांश पब्लिक स्कूलों में नौवीं कक्षा में तो एक भी भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जा रही। इनमें से कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें 12वीं में हिंदी का सेक्शन ही नहीं है, जबकि अंग्रेजी के अलावा बच्चों को पढ़ने के लिए जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश आदि विदेशी भाषाओं के विकल्प हैं। सरकारी स्कूलों में गनीमत है कि हिंदी बची हुई है, लेकिन ज्यादातर विज्ञान के विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में भी 11वीं में हिंदी नहीं पढ़ रहे या कहें उन्हें नहीं पढ़ाई जा रही। भाषा नीति के

> **आश्चर्य है कि दो-तीन विदेशी भाषाएं पढ़ना उन्हें अपने बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं लगता, लेकिन अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाएं सीखने के नाम पर वे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह अनुचित है। सरकार को किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए।**

नए आदेश का सबसे ज्यादा विरोध यही महंगे निजी स्कूल और अभिभावक कर रहे हैं। वे शिकायत कर रहे हैं कि इसे इस सत्र में ही लागू करना था तो पहली अप्रैल से क्यों नहीं किया गया। उन्हें पता होना चाहिए कि अप्रैल में शैक्षिक सत्र जरूर आरंभ हो जाता है, लेकिन पूरे देश में शिक्षा पहली जुलाई से ही शुरू होती है, इसलिए देरी की इस बात में कोई दम नहीं है। उनका दूसरा आरोप है कि हमने फ्रेंच, जर्मन भाषाओं की किताबें खरीद ली हैं और बच्चे कई वर्षों से इन भाषाओं को पढ़ रहे हैं। अब और भारतीय भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी तो उनके बच्चों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। यह उनकी दसवीं के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। उनकी यह भी शिकायत बचकानी है। उनसे बस यही कहना है कि अंग्रेजी तो वे जन्म से सीख रहे हैं। जर्मन और फ्रेंच भी उनको कभी अतिरिक्त बोझ नहीं लगते, पर अपनी मातृभाषा या अन्य देसी भाषाएं उन्हें बोझ क्यों लगने लगता है। क्या बच्चे अपनी मर्जी से जर्मन और दूसरी भारतीय भाषा सीखते हैं? नहीं। यह अभिभावकों और स्कूल का उन पर जबरदस्ती लदा हुआ बोझ है। क्या हमारा संविधान गलत है, जिसमें हिंदी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने और उसमें प्रशासन और शिक्षा देने की बात कही गई है? तीसरी भाषा के लिए सरकार ने सही राह सुझाई है कि इसमें बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, पाठ्यक्रम बहुत हल्का होगा और उसका मूल्यांकन भी आंतरिक होगा। इसका उद्देश्य साफ है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण की भाषाओं को जानें और दक्षिण के उत्तर भारत की। इससे दक्षिण का हिंदी और उत्तर भारत की भाषाओं का विरोध भी निर्मूल हो जाएगा और भाषाई एकता तो बढ़ेगी ही। आज यूरोप, अमेरिका से लेकर चीन, जापान जैसे देश इसलिए विकसित हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा और प्रशासन अपनी भाषा में होता है, अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषा में नहीं। तीसरी भाषा कौन-सी चुनी जाए। अच्छा तो यही रहेगा कि संस्कृत के नाम पर पुरानी गलती न हो। स्कूल या प्रशासन बच्चों की सहमति से भाषा का चुनाव करें। पंजाबी, मराठी देवनागरी परिवार की भाषा हैं। बच्चों को कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन क्या यही मेहनत दक्षिण के राज्यों को हिंदी सीखने के लिए नहीं करनी पड़ती? इसलिए बिना देरी के इस पर अमल होना चाहिए और जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी के अलावा दूसरी विदेशी भाषाएं भी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आसमान खुला है। बिना परीक्षा में शामिल किए यदि संभव हो तो स्कूल सिखाएं या कोई और इंतजाम करें। सब कुछ स्कूल नहीं सिखाते।

हमारे चारों तरफ ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने नौकरी, व्यवसाय के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से विदेशी भाषाएं सीखी हैं। इसलिए अभिभावकों का सरकार पर आरोप लगाना, उसे कठघरे में खड़ा करना या सुप्रीम कोर्ट जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। आश्चर्य है कि दो-तीन विदेशी भाषाएं पढ़ना उन्हें अपने बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं लगता, लेकिन अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाएं सीखने के नाम पर वे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह अनुचित है। सरकार को किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए।

लफ्ज़ों में जिंदगी की धड़कन छोड़ गए बशीर बद्र

बशीर बद्र अपने शब्दों में तन्हाई और पीड़ा को बखूबी उकेरते थे। वे चुभती जरूर थीं, मगर मन के किसी कोने दर्ज हो जाती थीं।

आम लोगों के जीवन के गहरे जख्मों को जीवंत शब्द देने वाले बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दिल को छू लेने वाली अपनी शायरी के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। वे जितने सरल थे, उनकी रचनाओं में उतनी ही सादगी और सहजता थी। उनमें इस कदर भाव अभिव्यक्त होते थे कि हर किसी को उनकी पंक्तियां अपनी-सी लगती थीं। आधुनिक गजल के इस उस्ताद के रचना संसार में जिंदगी का हर वह लम्हा था, जिसे मनुष्य जीता है। बशीर बद्र अपने शब्दों में तन्हाई और पीड़ा को बखूबी उकेरते थे। वे चुभती जरूर थीं, मगर मन के किसी कोने दर्ज हो जाती थीं। वे अपनी शायरी में उस शहर को भी जीते रहे, जहां अजनबियत बढ़ती चली गई थी। उन्होंने नए मिजाज के शहर को वक्त रहते पहचान लिया था। वे संघर्ष भरे रास्ते से गुजरे और जिंदगी की शाम आने से पहले उन्होंने लोगों की जुबान पर चढ़ जाने वाली कालजयी पंक्तियां रचीं। बशीर साहब के मशहूर शेर में समाज के जटिल ताने-बाने के बीच जद्दोजहद करने का जज्बा दिखता है। उनमें जिंदगी के कई पाठ हैं। उनकी शायरी हमें जीने का रास्ता दिखाती है। हममें से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी मौके पर उनकी शायरी को याद करते रहे और उन्हें दोहराते रहे हैं। जीवन में संवेदनात्मक उतार-चढ़ाव के वक्त न जाने के कितने लोगों ने उनकी शायरी को अपना सहारा बनाया होगा। बशीर बद्र अपने जीवन में जिस मुकाम पर पहुंचे, वहां तक पहुंचना कोई आसान नहीं था। अपने दम पर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाया। हिंदी और फारसी पर उनकी गहरी पकड़ थी। वे उर्दू तक सीमित नहीं रहे। उनकी कई रचनाओं का अनुवाद हुआ और दुनिया भर में वे मशहूर हुईं। कई बड़े पुरस्कारों से नवाजे गए बशीर हमेशा विनम्र रहे। दुनिया को मुसाफिरखाना मानने वाले बशीर बद्र के निधन से उनके प्रशंसक दुखी हैं। निस्संदेह उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है, जिन्हें आधुनिक शायरी का नगीना माना गया। सच यह है कि बशीर बद्र एक ऐसे शायर थे, जिनके शब्द भावों की गहराई लेकर दिलों में धड़कते हैं। मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने की खबर से साहित्य और गजल प्रेमियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। जावेद अख्तर समेत तमाम लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। उर्दू शायरी में बशीर बद्र का नाम बड़े और मशहूर गजलकारों में लिया जाता था। उनकी शानदार शायरी और साहित्य में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया था। उर्दू शायरी की दुनिया में वह एक शानदार नाम थे। उनकी मौत पर बॉलीवुड के लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी दुख जताया।

कठिनाइयां ही हमें असाधारण बनाती हैं, बहाने छोड़ आगे बढ़ें

अगर रास्ता कठिन न हो, तो मंजिल की कीमत भी कम हो जाती है। इसलिए कठिनाई से घबराएं नहीं। उसका स्वागत करें, क्योंकि वही आपको साधारण से असाधारण बनाती है।

जब खेल आसान हो, तब मैदान में उतरना बड़ी बात नहीं। असली पहचान तब होती है, जब आसमान धुंधला हो, शरीर थक चुका हो, भीड़ की आवाज धीमी पड़ जाए और स्कोरबोर्ड तुम्हारे खिलाफ खड़ा दिखाई दे। वही क्षण आदमी को बताता है कि वह वास्तव में कौन है। मैंने अपने खिलाड़ियों से हमेशा कहा है कि तुम्हारी ताकत इस बात से नहीं देखी जाएगी कि तुमने कितनी बार जीत हासिल की, बल्कि इस बात से देखी जाएगी कि हार सामने खड़ी होने पर भी तुमने अपने कदम कितनी मजबूती से रखे। सामान्य दिनों में तो हर कोई आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है, लेकिन मुश्किल दिन ही आदमी के भीतर छिपी ताकत और साहस को बाहर निकालते हैं। तुम मैदान में उतरते हो, तो केवल गेंद लेकर नहीं उतरते। तुम अपने परिवार की उम्मीदें और इससे भी ज्यादा अपने भीतर उस छोटे-से विश्वास को लेकर उतरते हो, जो यह कहता है कि- 'मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं।' मैंने ऐसे खिलाड़ियों को देखा है, जो शरीर से तो लंबे-चौड़े-बलिष्ठ थे, पर संकट आते ही उनका साहस डगमगाने लग जाता था। जीत केवल ताकत से नहीं मिलती, जीत तो उस आदमी के हिस्से आती है, जो कठिनाई को देख कर पीछे नहीं हटता। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, तब दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वे लोग जो बहाने खोजते हैं, जैसे- मौसम खराब था, किस्मत साथ नहीं थी। और दूसरे वे लोग, जो अपने जूतों के फीते कसते हैं और कहते हैं 'अब मेरी बारी है यह दिखाने की कि मैं किस मिट्टी का बना हूं।' एक समय के बाद मन हार मानने के लिए बहाने देने लगता है। तभी चरित्र खेल में उतरता है। चरित्र वह शक्ति है, जो कहती है 'एक कदम और।' और वही अतिरिक्त कदम इतिहास बनाता है। जीवन कठोर है। कभी पूरी तैयारी के बाद भी हार जाओगे। कभी तुम्हारे अपने साथी तुम्हें कमजोर कहेंगे। लेकिन यह तो तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी आत्मा का कप्तान कौन है- हालात या तुम स्वयं। तूफान जब आता है, तब कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ और गहरे धंस जाते हैं। आदमी भी ऐसा ही है। संकट उसे तोड़ता नहीं, संकट उसके भीतर की असली ताकत को बाहर लाता है। मैंने अपने खिलाड़ियों से हमेशा यही कहा- भीड़ की आवाज को मत सुनो। केवल अपने भीतर की आवाज सुनो। अगर तुम्हारा मन अभी भी लड़ने को तैयार है, तो खेल समाप्त नहीं हुआ। अगर रास्ता कठिन न हो, तो मंजिल की कीमत भी कम हो जाती है। इसलिए कठिनाई से घबराओ मत। उसका स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। लोग तुम्हें तुम्हारी आसान जीतों से कुछ समय के लिए याद रखेंगे, लेकिन वे तुम्हें हमेशा उस साहस के लिए याद रखेंगे, जो तुमने सबसे कठिन क्षणों में दिखाया था। इसलिए जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब सिर झुका कर मत बैठो। दुनिया को बता दो कि मजबूत लोग कठिनाइयों से भागते नहीं, वे कठिनाइयों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वही क्षण उन्हें महान बनाते हैं। जब आसमान धुंधला लगे, तब याद रखना कि असली पहचान जीत में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में है, जिससे तुम हार के सामने खड़े रहते और भीतर की आवाज सुनकर एक कदम और बढ़ाते हो, क्योंकि कदम तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। इसलिए बहाने छोड़ आगे बढ़ें, क्योंकि संकट तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आता है। आप अपने जीवन के कप्तान खुद बनें।

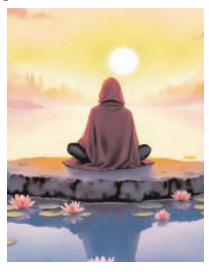

सिर्फ घुसपैठ नहीं, भीतर तक फैलता सुरक्षा का खतरा

पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ और इससे जुड़ी आतंकवाद की समस्या ने भारत को किस स्तर तक नुकसान पहुंचाया है, यह छिपा नहीं है। हालांकि सीमा पर तैनात सुरक्षा बल के जवान अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी ठिकानों से भारत में घुसपैठ करने वालों को रोकें, गिरफ्तार करें या फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें निशाना बनाया जाए। विडंबना यह है कि आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी का तंत्र अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होने को माना जाता रहा है। फिर सीमा पर स्थित रिहाइशी इलाकों में भी कई बार आतंकी सूत्रों से जुड़े लोगों की पहचान नहीं पाने के अपने जोखिम हैं। शायद यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने साफ लहजे में पाकिस्तान सीमा के आसपास सुरक्षा के लिहाज से सख्त नीति अपनाने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाके के आसपास के जिलों में सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय बैठक में भारत और पाकिस्तान सीमा के आसपास चौतरफा सुरक्षा योजना के तहत कई अहम निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक, अब सीमा से पंद्रह किलोमीटर तक के क्षेत्र में हर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और शून्य सहनशीलता की नीति के तहत ऐसे निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। इस सख्ती की वजह मुख्य रूप से राजस्थान के सीमाई इलाके के जिलों में घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना है। यह छिपा नहीं है कि सीमा से सटे क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से अलग-अलग रूप में होने वाली घुसपैठ अंतिम तौर पर भारत में आतंकवाद की जड़ों को मजबूत करती है। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से रहने वाले कुछ लोग कई बार आतंकियों के लिए अप्रत्यक्ष सहायक के रूप में काम करते हैं। इनमें से कई लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेकर न केवल स्थानीयता का फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं, बल्कि संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, अवैध गतिविधियों और सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी में भी लिप्त होते हैं। यह अकारण नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ चलने वाले अभियान के सामने अक्सर आंतरिक मोर्चों पर खड़ी जटिलताएं एक बड़ी चुनौती होती हैं।

विधानसभा के गेटों के नामकरण किये जाने वाले नवाचार की मेघवाल ने प्रशंसा की

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मुलाकात

देवनानी ने मेघवाल को विधानसभा का प्रतीक चिन्ह भेंट किया

देवनानी की मेघवाल से विभिन्न विषयों पर चर्चा

जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय विधि एवं न्याय,संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल की यहां सिविल लाइन स्थित राजकीय निवास पर मुलाकात हुई। श्री मेघवाल रविवार को अजमेर जाते वक्त जयपुर एयरपोर्ट से देवनानी के आवास पर पहुंचे।

स्पीकर देवनानी ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर और शाल ओढ़ाकर अभिवादन किया।देवनानी ने मेघवाल को राजस्थान विधानसभा का प्रतीक चिन्ह स्मृति स्वरूप भेंट किया।देवनानी ने मेघवाल को अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक की प्रति भेंट की।

विधानसभा का प्रतीक चिन्ह जन मानस की सोच का प्रतिनिधित्व

अर्जुन राम मेघवाल ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पहल की सराहना करते हुए विधानसभा के लोगो को राजस्थान के जन मानस की सोच का प्रतिनिधित्व बताया।उन्होंने प्रतीक चिन्ह में सम्मिलित राज्य वृक्ष खेजड़ी और विधान सभा भवन की छवियों की चर्चा करते हुए कहा कि यह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्सवधर्मिता से जीवन जीने वाले लोगों की जीवटता को दर्शाता है। ऊंट और गोडावन का समावेश समन्वय की संस्कृति का द?योतक है। 'राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका राजस्थान विधान सभा द्वारा की जाने वाली जनसेवा और संवैधानिक मर्यादा का आत्म मंत्र है।लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति कर्तव्यों में ही होती है।

मेघवाल ने देवनानी के नवाचारों की सराहना की

मेघवाल ने स्पीकर देवनानी के विधानसभा भवन के विभिन्न द्वारों के नामकरण को ऐतिहासिक और मूल्यपरक निर्णय बताते हुए कहा कि द्वारों के नाम लोकतंत्र के मूल आदर्शों के प्रतीक हैं। इन ?द्वारों से प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि वह केवल एक भवन में नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक संस्कारों के पवित्र केंद्र में प्रवेश कर रहा है। मेघवाल ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न भवनो के नामकरण करने की तर्ज पर देवनानी ने विधानसभा के द्वारों को कर्तव्य द्वार,शक्ति द्वार,सुशासन ?द्वार, संकल्प द्वार और शौर्य द्वार नाम देकर ऐतिहासिक कार्य किया है। मेघवाल ने विधान सभा भवन के बाहरी ?द्वारों को राजस्थान के अंचलो बृज, शेखावाटी, वागड़, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा और ढूंढाड़ के नाम समर्पित कर, राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और लोकपरंपराओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ने का अभिनव प्रयास बताया। देवनानी की मेघवाल से संसदीय कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर देश की न्याय व्यवस्था,विधिक सुधारों, संवैधानिक विषयों तथा विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई।कानून के प्रभावी क्रियान्वयन,सुशासन एवं जनहित से जुड़े विषयों पर भी बातचीत हुई।

चौहटन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: स्मैक और एमडी ड्रग के साथ युवक गिरफ्तार

54.34 ग्राम स्मैक और 51.34 ग्राम एमडी बरामद; बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर नशा सप्लाई करने की फिराक में था आरोपी

जयपुर।

जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्त बाड़मेर अभियान के तहत चौहटन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 54.34 ग्राम स्मैक, 51.34 ग्राम एमडी ड्रग तथा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद ड्रग की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य एवं वृताधिकारी चौहटन जेठाराम के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस मुख्यालय एवं जोधपुर रेंज के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी चौहटन ललित किशोर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कस्बा चौहटन में संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की।

पुलिस ने आरोपी वीराराम पुत्र नारायणराम प्रजापत (21) निवासी चौहटन को हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 54 ग्राम 34 मिलीग्राम स्मैक तथा 51 ग्राम 34 मिलीग्राम एमडी बरामद हुई। साथ ही एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।

इस संबंध में पुलिस थाना चौहटन में दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, आपूर्ति नेटवर्क तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है।

इस कार्रवाई में कांस्टेबल पदमाराम (1739) की विशेष भूमिका रही, जिनकी सतर्कता और सूचना संकलन से सफलता मिली। पुलिस टीम में एसएचओ ललित किशोर सहित कांस्टेबल रमेश कुमार, देवाराम, पदमाराम रोशन कुमार मीणा और विकास शर्मा शामिल थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों से पेयजल प्रबंधन में बड़ा सुधार

छह विशेष अभियानों में 15,995 शिकायतों का समाधान,हजारों परिवारों को मिली राहत

जयपुर।

प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आमजन को निर्बाध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा संचालित छह विशेष राज्यव्यापी अभियानों के माध्यम से अब तक 15,995 पेयजल संबंधी शिकायतों एवं समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।

जन राहत का प्रभावी माध्यम बने विशेष अभियान

प्रदेशभर में संचालित अभियानों के दौरान 3,077 हैंडपंपों की मरम्मत, 1,644 पाइपलाइन लीकेज की दुरुस्ती, 978 प्रेशर संबंधी समस्याओं का समाधान तथा 1,144 बाधित जलापूर्ति क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बहाल की गई। इसके अतिरिक्त 230 कम अवधि वाली जलापूर्ति, 544 कम सप्लाई एवं 121 प्रदूषित जल संबंधी शिकायतों का भी निस्तारण किया गया। विभाग ने 1,401 अवैध जल कनेक्शन हटाने के साथ 6,827 अन्य पेयजल सुधार कार्य भी पूर्ण किए हैं।

विशेष टीमों ने मौके पर किया त्वरित समाधान

अभियान के तहत गठित विशेष टीमों ने शनिवार को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। छठे विशेष अभियान में 639 खराब हैंडपंपों को पुनः चालू किया गया, 455 पाइपलाइन लीकेज ठीक किए गए तथा 220 प्रेशर संबंधी शिकायतों का समाधान किया गया। साथ ही 242 क्षेत्रों में बाधित जलापूर्ति बहाल कर आमजन को राहत पहुंचाई गई।

3,077 हैंडपंप और 1,644 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त

अप्रैल से जारी अभियान दे रहे हैं सकारात्मक परिणाम

5 अप्रैल से 23 मई तक संचालित पांच विशेष अभियानों के दौरान 2,438 हैंडपंपों की मरम्मत, 1,189 पाइपलाइन लीकेज की दुरुस्ती, 758 प्रेशर समस्याओं का समाधान, 902 जलापूर्ति बाधित मामलों का निस्तारण, 180 कम अवधि वाली जलापूर्ति, 416 कम सप्लाई, 95 प्रदूषित जल संबंधी शिकायतों का समाधान तथा 6,277 अन्य सुधार कार्य किए गए। इसी अवधि में 1,065 अवैध जल कनेक्शन भी हटाए गए।

अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई

जल संरक्षण और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। छठे अभियान के दौरान 336 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए, जिनमें होटल, ढाबे, सरस डेयरी बूथ तथा कृषि कार्यों में उपयोग किए जा रहे कनेक्शन शामिल थे। इस कार्रवाई से पेयजल की बर्बादी रोकने और आमजन के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत हुई जलापूर्ति व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों एवं पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत के साथ 550 अन्य पेयजल सुधार कार्य भी पूर्ण किए गए। इन प्रयासों से हजारों ग्रामीण परिवारों को राहत मिली है तथा जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है।

2,600 शिकायतों का मौके पर समाधान

पीएचईडी की तकनीकी टीमों ने अभियान के दौरान प्राप्त लगभग 2,600 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर आमजन को तत्काल राहत प्रदान की। विभाग की सक्रियता से पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर संचालित यह विशेष अभियान संभावित पेयजल संकट को कम करने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहे है। राज्य सरकार का लक्ष्य गर्मी के मौसम में प्रदेश के प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर तक पर्याप्त, नियमित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।

हर गांव और हर शहर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर संचालित यह विशेष अभियान संभावित पेयजल संकट को कम करने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहे है। राज्य सरकार का लक्ष्य गर्मी के मौसम में प्रदेश के प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर तक पर्याप्त, नियमित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम से मिलता है राष्ट्र निर्माण और जनसेवा का प्रेरक संदेश:मदन राठौड़

जयपुर।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रत्येक संस्करण देशवासियों को प्रेरणा,ज्ञान और सकारात्मक सोच का संदेश देता है।रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम के 134वें संस्करण का सामूहिक श्रवण करने के बाद राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार समाज को नई दिशा देने वाले हैं तथा जनभागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की प्रतिभाओं,नवाचार,युवा शक्ति,स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा जनसहभागिता से होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में दौड़ प्रतियोगिता में 10.1 सेकंड में रिकॉर्ड बनाने वाले प्रतिभाशाली युवाओं की चर्चा कर प्रधानमंत्री ने देश की उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी के दौर में शरबत एवं पारंपरिक पेय पदार्थों के महत्व, पेयजल संरक्षण,जल संचयन,जल संकट के समाधान,नदियों की स्वच्छता, तैराकी सीखने तथा दिव्यांगजनों को तैराकी से जोड़ने जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण संदेश दिए।इसके साथ ही आम सहित भारतीय फलों और स्थानीय उत्पादों के महत्व का उल्लेख कर 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को और मजबूत किया।राठौड़ ने कहा कि 'मन की बात' केवल एक कार्यक्रम नहीं,बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा देने वाला अभियान है।इससे देशभर के लोगों के उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी मिलती है और जनसेवा के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होती है।उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से यदि अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं तो यह लोकतंत्र और समाज के लिए स्वागतयोग्य बात है। राठौड़ ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम में कई युवा, सेवानिवृत्त कर्मचारी साइकिल से कार्यालय पहुंचे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजनीति में मर्यादित भाषा और स्वस्थ संवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए राठौड़ ने कहा कि शब्दों की गरिमा लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। विपक्ष का दायित्व सरकार का विरोध करना है और प्रबलता से अपनी बात रखना लोकतंत्र का हिस्सा है,लेकिन शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि भाषा की शालीनता और संवाद की संस्कृति को बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता सशक्त विपक्ष और स्वस्थ राजनीतिक विमर्श में निहित है।विचारों का मतभेद लोकतंत्र की शक्ति है,लेकिन व्यक्तिगत कटुता और अमर्यादित शब्दावली लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। इसलिए राजनीतिक जीवन में संयमित भाषा,शिष्टाचार और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में गृहराज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पूर्व नेताप्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ , भाजपा महामंत्री भूपेंद्र सैनी, सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह, अजीत मांढण, मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, सह प्रभारी भवानी शंकर शर्मा, भाजपा आईटी प्रभारी अविनाश जोशी सहित प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा, प्रकोष्ठ और विभागों के अध्यक्ष–संयोजक तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जयपुर जिले में 3500 से अधिक नागरिकों ने निभाई सहभागिता

जल जागरुकता प्रभात फेरियो साइकिल रैलियों, पेयजल व्यवस्थाओं सहित विभिन्न गतिविधियों का हो रहा आयोजन

जयपुर।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 के अंतर्गत ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को जयपुर जिले में विभिन्न विभागों,पंचायत समितियों,नगरीय निकायों,स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं आमजन की सक्रिय सहभागिता से जल संरक्षण,स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रातःजिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र, चौगान स्टेडियम से वंदे गंगा पैदल रैली एवं साइ?किल रैली का आयोजन किया गया। रैली को खेल अधिकारी मानसिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों को जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई।पंचायत समिति शाहपुरा क्षेत्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कुल 61 गतिविधियों का आयोजन किया गयाए जिनमें लगभग 2068 नागरिकों ने भागीदारी निभाई।क्षेत्र में प्रभात फेरियां, जनजागरूकता रैलियां एवं साइकिल रैलियां आयोजित कर जल संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुँचाया गया।

शाहपुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुरा में ग्रामीणों एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पौधारोपण,जल संरक्षण संरचनाओं की साफ सफाई, श्रमदान,डी सिल्टिंग तथा स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया।ग्रामवासियों ने सामुदायिक श्रमदान के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने का संकल्प लिया। पंचायत समिति मौजमाबाद की समस्त ग्राम पंचायतों में वंदे गंगा जल जागरुकता रैली एवं साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में लगभग 125 जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण,पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी के महत्व पर विशेष जागरुकता गतिविधियां संचालित की गई।

कोटखावदा ब्लॉक में प्रभात फेरी,जागरूकता रैली एवं साइकिल रैली का आयोजन किया

गया,जिसमें लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

नगर पालिका दूदू क्षेत्र में वंदे गंगा प्रभात फेरी,जागरूकता रैली. जल स्रोतों की साफ सफाई,बावड़ियों एवं खेलियों की सफाई.जल सेवा,परिंडे स्थापना,पशुओं हेतु पेयजल व्यवस्था,हनुमान सागर बांध पर दीप प्रज्वलन तथा नो-प्लास्टिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में लगभग 450 नागरिकों ने भाग लिया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भी स्वच्छता एवं जनजागरुकता गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई।

नगर पालिका चाकसू में मनोहरा तालाब एवं गोलीराव तालाब पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। विभिन्न स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई तथा कपड़े के शैलों का वितरण कर प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली का संदेश दिया गया। फागी मोड़, राजकीय अस्पताल, अंबेडकर सर्किल, गरुड़वासी मोड़ एवं चाकसू रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कार्यक्रमों में लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अभियान के अंतर्गत जिलेभर में जल संग्रहण संरचनाओं की गाद निकासी डी सिल्टिंग), जल स्रोतों एवं बावड़ियों की साफ सफाई, पशु खेलियों का रखरखाव, जल सेवा, परिंडे स्थापना पशुओं हेतु पेयजल व्यवस्था महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई, दीप प्रज्वलन पौधारोपण की पूर्व तैयारी तथा नो प्लास्टिक डे के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे के निस्तारण जैसी गतिविधियां आयोजित की गई।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जयपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायर्यों में आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 3500 से अधिक नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों कर्मचारियों स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं स्वयंसेवकों ने सहभागिता निभाई। पंचायत समिति शाहपुरा क्षेत्र में सर्वाधिक 61 गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिलेभर में आयोजित इन गतिविधिर्या के माध्यम से जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरुकता बढ़ाने तथा जनभागीदारी को सुदृढ़ करने का सफल प्रयास किया गया।

औद्योगिक विकास को रफ्तार : रिडको की भूमि आवंटन नीति से राजस्थान में बढ़ेगा निवेश

रिडको की भूमि आवंटन नीति को हरी झंडी

औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित

लोक टूडे। जयपुर

राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रिडको) की भूमि आवंटन एवं भूमि मूल्य निर्धारण नीति को स्वीकृति मिल गई है। जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखण्ड आवंटन, प्रबंधन एवं निस्तारण हो सकेगा। नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष आवंटन योजना या अन्य माध्यमों से भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, एफडीआई परियोजनाओं एवं अन्य निवेशों के लिए भूखण्ड आवंटन की विशेष प्रक्रिया एवं ई-नीलामी की व्यवस्था आदि का प्रावधान किया गया है। एनआईसीडीसी द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित यह नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं एवं निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। दिल्ली- मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित किए जा रहे पांच नोड में से एक नोड जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि जोधपुर से 22 किमी एवं पाली से 40 किमी की दूरी पर स्थित तहसील रोहट की भूमि पर रिडको द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 एवं राज्य राजमार्ग 64 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से इस क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु एनएचएआई के द्वारा अण्डरपास का निर्माण किया गया है। लगभग 823 रूपये करोड़ की राशि से रोहट और मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन की दोहरीकरण की योजना को रेलवे बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को गैस उपलब्ध करवाने हेतु 4.5 किमी लंबाई में गैस पाइप लाइन तथा पाली और जोधपुर को जोड़ने वाली गैस ग्रिडलाइन महसाना-भटिण्डा से डालने की परियोजना तैयार कर ली गई है। रिडको, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, भारत सरकार एवं रीको के संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित कंपनी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं आधारभूत संरचना का विकास करना है।

इंडस्ट्रियल एरिया में आधारभूत सुविधाएं विकसित

राजस्थान में विकसित किये जा रहे प्रथम नोड जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु रिडको द्वारा राशि रूपये 370 करोड़ का कार्यादेश दिसंबर 2025 में जारी किया गया है जिसके अंतर्गत कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रीको द्वारा इस क्षेत्र में विद्युत एवं जल उपलब्धता हेतु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से डिपोजिट वर्क करवाये जा रहे हैं। दोनों ही विभागों द्वारा संबंधित कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं।

अग्रिम भुगतान करने पर रियायत

रिडको के अंतर्गत जेपीएमआईए फेज-प्रथम में कुल बिक्री योग्य भूमि क्षेत्र लगभग 1186 एकड़ हैं। प्रारंभिक निवेशकों द्वारा अग्रिम भुगतान करने पर रियायती दर/छूट, आगामी वर्षों में भूमि दरों की चरणबद्ध बढ़ोतरी तथा 11 त्रैमासिक ब्याजयुक्त किस्तों के माध्यम से स्थगित

भुगतान की व्यवस्था भी नीति के अंतर्गत रखी गई है।

99 वर्ष की लीज पर मिलेंगे भूखण्ड -

प्रस्तावित नीति में सामान्यत: भूखण्डों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग-एंड-प्ले, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लचीली लीज अवधि तथा नवीनीकरण का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पूर्व-निर्मित औद्योगिक अवसंरचना, आवासीय एवं सामाजिक अवसंरचना हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग सुविधाओं तथा उपयोगिताओं एवं सहायक सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

क्षेत्र का होगा चहुंमुखी विकास -

रीको के प्रबन्ध निदेशक एवं रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सुरेश ओला ने बताया कि रिडको, जेपीएमआईए की औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के प्रथम चरण में चिन्हित औद्योगिक भूखण्डों के सीमांकन के तुरंत बाद उनका आवंटन प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। इस क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। सेक्टर विशेष जोन भी स्थापित होंगे जिससे इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो सकेगा। रिडको की भूमि आवंटन नीति से राजस्थान में निवेश बढ़ने, औद्योगिक विकास को गति मिलने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

बीजेपी की 'किफायत' हवा-हवाई, तेल फूंकते पहुंचे नेता; सिर्फ एक ने की कार पूलिंग

लोक टूडे। जयपुर

राजस्थान में रविवार को बीजेपी कार्यालय से लेकर बूथ स्तर पर पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में पहुंचने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पार्टी ने अपील की थी कि वे ईवी, साइकिल, कार पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन (सरकारी बस) और संभव हो सके तो पैदल चलकर पहुंचे। जिससे लोगों को वैश्विक संकट के समय किफायत बरतने का ठोस संदेश दिया जा सके। लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों ने ही पार्टी की अपील को दरकिनार कर दिया। कुछ पदाधिकारियों और नेताओं को छोड़कर अधिकतर हमेशा की तरह अपनी पेट्रोल-डीजल की गाड़ी से ही कार्यालय पहुंचे।

केवल एक पदाधिकारी को छोड़कर किसी ने भी कार पुलिंग का इस्तेमाल नहीं किया। सभी लोग अपनी गाड़ी में अकेले बैठकर बीजेपी कार्यालय आए। कोई भी ऐसा नहीं था जो साइकिल, सार्वजनिक परिवहन या पैदल पहुंचा हो।

ये नेता अपनी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से पहुंचे :

प्रदेश पदाधिकारियों में महामंत्री भूपेन्द्र सैनी, प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह, प्रदेश मंत्री एकता

अग्रवाल, प्रदेश मंत्री अजीत मांडन, पूर्व प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ज्योति खंडेलवाल, जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष अमित गोयल, प्रदेश मीडिया संजोयक प्रमोद वशिष्ठ सहित अधिकतर पदाधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता और नेता अपनी-अपनी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से पहुंचे। किसी ने भी ईवी कार, ई-रिक्शा, कार पुलिंग और साईकिल का इस्तेमाल नहीं किया।

नेशनल असेसमेंट की टीम ने किया सीएचसी चौमहला का निरीक्षण

लोक टूडे। झालावाड़

झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक की सीएचसी चौमहला में नेशनल असेसमेंट की टीम के द्वारा 2 दिवसीय निरीक्षण किया गया, जिसमें नेशनल असेसर राजेश सैनी व हर कोमल शर्मा ने 9 विभागों का निरीक्षण किया गया। इसमें ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, लेबोरेटरी, रेडियोलोजी, लेबर रूम, फार्मेसी, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीलरी सर्विसेज के अलावा पूरे हॉस्पिटल परिसर, गार्डन एरिया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, टीकाकरण कक्ष, वेटिंग एरिया का भी गहनता के साथ निरीक्षण किया। नेशनल असेसमेंट से संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर, फाइल्स, पॉलिसीज़ को जांचा गया। विजिट के दौरान डॉ. अरविंद नागर, डॉ. राजकुमार बघेला, डॉ दिलीप मीणा, डॉ अर्पित गुप्ता, डॉ योगेन्द्र कुमार, रवि कुमार अग्रवाल, प्रह्लाद प्रजापति,

जगदीश मेहर, राकेश सुमन, राजेश सेन, गोपाल सिंह, अमीत शर्मा, सन्तोष कुमार, महेश कँवल, विकास भादल, सचिन झाला, आस्था पाटीदार, संतोष, लक्ष्मी एएनएम, उर्मिला पंथी एएनएम, पूजा एएनएम, अनीता, सुनीता एलटी, आशीष, कुंदन विशल, आबीद खान, अक्षय नामा, मोहित प्रजापत, महेश मीना, दिनेश मकवाना, आशीष शर्मा, अजय शर्मा, वेकटेश शर्मा, विकास शर्मा, मुकीम अहमद, कजोड़ बैरागी, अश्विन नायक, अनिल राजोरिया, सुनील राजोरिया, शेलेन्द्र राजोरिया, कान्ता बाई, राजबहादुर, भुरिया, काजु जैन अन्य समस्त सीएचसी स्टाफ मौजूद रहा।

सिविल लाइंस कार्यालय में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुनी 'मन की बात'

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा हर बार मिलता है कुछ नया सीखने का अवसर

जयपुर।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को सिविल लाइंस कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का श्रवण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत 'मन की बात' कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला प्रेरणादायी मंच है।कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सेवा, नवाचार,आत्मनिर्भरता,जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े अनेक प्रेरक विचार साझा किए, लजो समाज के प्रत्येक वर्ग को देशहित में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हर बार की

तरह इस बार भी 'मन की बात' से कुछ नया सीखने को मिला।कार्यक्रम के माध्यम से नई जानकारियां प्राप्त होती हैं और नवाचारों से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं।

हादसे रोकने 5 वर्ष में 501 करोड़ रुपए खर्च, 2025 में 24 हजार हादसों में 12 हजार मौतें

जयपुर

परिवहन विभाग रोड सेफ्टी पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हादसों और मरने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए अलग से विंग बना रखी है। इसके तहत पिछले 10 साल से रोड सेफ्टी पर काम किया गया। इसके बावजूद भी सड़क हादसों और मौतों में कमी होने की अपेक्षा बढ़ोतरी हो रही है। पिछले पांच साल में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग करीब 501 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इसके बावजूद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। हादसों में कमी होने की अपेक्षा बढ़ोतरी हो रही है। हादसों में 25 से 35 उम्र वाले युवा सबसे अधिक असुरक्षित वाहन चला रहे हैं। इस वजह से इस उम्र के युवाओं की सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। इस उम्र के युवाओं की 31 प्रतिशत, 18 से कम उम्र के युवाओं की 6 प्रतिशत, 18 से 25 उम्र के युवाओं की 24 प्रतिशत, 35 से 45 उम्र के 24 प्रतिशत, 45 से 60 उम्र के 12 प्रतिशत, 60 से अधिक उम्र वाले लोगों की मौत 3 प्रतिशत हो रही है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रतिभाशाली युवाओं का किया सम्मान

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं

जयपुर।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को जयपुर में श्री खंडेलवाल वैश्य एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की।इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाज और राष्ट्र के विकास में युवा शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान न केवल उनके परिश्रम और उपलब्धियों को नई पहचान देता है,बल्कि अन्य युवाओं को भी उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है।

कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला न्यायाधीश अनिल कुमार, आर.सी. गुप्ता, एस.एन. गुप्ता, ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश चंद गुप्ता, संरक्षक सोहनलाल ताम्बी, कृष्ण मोहन,गोविंद शरण धामाणी, मुरारी लाल गुप्ता,विष्णु प्रसाद महरवाल, पंकज कट्टा, प्रिंसिपल अंजु गुप्ता, समाजसेवी सत्यनारायण, राजेश ताम्बी, अभीभावकगण, छात्र एवं छात्राएं अपस्थित रहे।